

भारतीय डाक विभाग की सेवाओं एवं जमा योजनाओं का आर्थिक अध्ययन (बिलासपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

शोध निर्देशक

डॉ. राजेश कुमार शुक्ला

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

सी.एम.दुबे पी.जी. महाविद्यालय

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

शोधार्थी

सत्या कुर्रे

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

वीरांगना अवंती बाई लोधी

शासकीय महाविद्यालय, पथरिया,

मुंगेली (छत्तीसगढ़)

सारांश

यह अध्ययन भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और जमा योजनाओं का आर्थिक विश्लेषण करता है, विशेष रूप से बिलासपुर जिले के संदर्भ में। भारतीय डाक विभाग एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो न केवल डाक और संचार सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि बचत खाते, सार्वजनिक भविष्य निधि और विभिन्न जमा योजनाओं जैसी वित्तीय सेवाओं की भी पेशकश करता है। यह शोध इन सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार को उजागर करता है, जो स्थानीय जनसंख्या में वित्तीय समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सेवाओं का बिलासपुर जिले के आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। हालांकि, इसके लाभों के बावजूद, अध्ययन में तकनीकी बाधाएं, संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी, और निजी वित्तीय संस्थानों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों की पहचान की गई है। इन मुद्दों का समाधान करना डाक सेवाओं की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। भारतीय डाक विभाग अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और समुदाय की सेवा करने में सक्षम हो सकता है, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकता है।

मुख्य बिंदु : भारतीय डाक विभाग, सेवाएँ, जमा योजनाएँ, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बचत खाता है।

प्रस्तावना

भारतीय डाक विभाग देश की रीढ़ है, जिसने डाक सेवा के माध्यम से संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान किया है। यह विभाग भारतीय नागरिकों के जीवन से जुड़े कई पहलुओं को छूता है, जैसे मेल डिलीवरी, लघु जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के माध्यम से जीवन बीमा प्रदान करना। इसके अलावा, भारतीय डाक विभाग बिल जैसी रिटेल सेवाएं प्रदान करता है, संग्रह करता है और प्रपत्रों की बिक्री करता है। भारतीय डाक विभाग भारत सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वेतन वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के लिए एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय डाक विभाग 1,55,531 पोस्ट कार्यालयों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा डाक वितरण नेटवर्क संचालित करता है।

सन् 1727 में कोलकाता में पहले डाकघर की स्थापना के साथ भारतीय डाक विभाग की शुरुआत हुई। डाकघर आज ग्राहकों को डाक, पार्सल, धनांतरण, बैंकिंग, बीमा और रिटेल जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है। डाक विभाग ने "दर्पण परियोजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य विभाग को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की है ताकि कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन मिले। वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ, डाक विभाग संचार सेवाएं भी प्रदान करता है और बचत बैंक की सुविधा उपलब्ध कराता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह विभाग कई छोटी बचत योजनाओं को लागू करता है, जो देशभर में 1.55 लाख डाकघरों से संचालित होती हैं। इन योजनाओं में मासिक आय योजना, सावधि जमा, बचत खाता, आवर्ती जमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को छोटी बचत के लिए प्रेरित करना है, जिससे निवेशकों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।

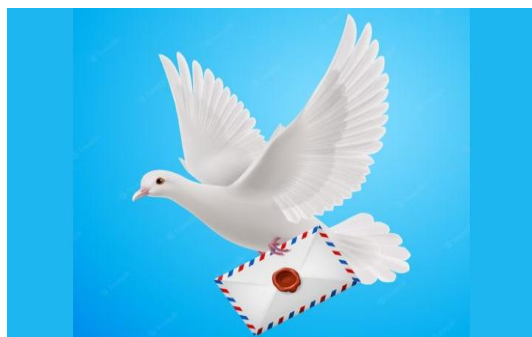
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय डाक विभाग की डाक प्रणाली को जानने हेतु इसकी ऐतिहासिक विवरण को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें मौर्य काल, मुगलकाल तथा ब्रिटिश काल में बांटा गया है।

मौर्य काल के दौरान डाक प्रणाली (321BC–297BC)

भारत में प्रारंभिक डाक प्रणाली का अस्तित्व सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाया जा सकता है, उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। जिसके कारण राजधानी का प्रांतीय शासकों के साथ संचार के उचित साधन उपलब्ध ना होने के कारण प्रशिक्षित कबूतरों का उपयोग संचार हेतु किया जाने लगा। जिससे राजधानी और प्रांतीय शासन के बीच सुगम संचार साधन स्थापित होने लगा।

कबूतर डाक व्यवस्था सम्राट अशोक के काल में भी जारी रहा। कबूतर डाक व्यवस्था प्रशिक्षित कबूतरों के पैरों में छोटी-छोटी थैलियों में पत्र बाँधे जाते थे जिन्हें उड़ाया जाता था, जिससे उन्हें विशिष्ट गंतव्यों तक भेजा जाता था, और इस तरह विभिन्न प्रकार महत्वपूर्ण संदेश भेजे जाते थे। मुगल काल के दौरान डाक व्यवस्थाएँ, ब्रिटिश काल 1854 के पहले डाक व्यवस्था, 1774 कोलकाता जीपीओ की स्थापना, 1786 में मद्रास जीपीओ की स्थापना, 1794 में बॉम्बे जीपीओ की स्थापना, बेंगलोर जी.पी.ओ की स्थापना लगभग 1800 हुई है।



भारत में डाक सेवा का विकास

भारतीय डाक सेवाएँ विश्व का विशालतम डाक सेवा हैं। यह वर्ष 1727 में प्रारंभ हुआ। प्रथम डाक घर पश्चिम बंगाल राज्य के कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया। तत्पश्चात् भारत के तीन प्रेसीडेंसी टाउन मद्रास, बाम्बे और दिल्ली में जनरल पोस्ट ऑफिस (जी.पी.ओ.) स्थापित किये गये। इन चारों शहरों के डाकघरों में एकरूपता स्थापित करने के लिए डाक अधिनियम 1854 बनाया गया जा कि वर्तमान में भारतीय डाक प्रणाली का मुख्य आधार है। इन अधिनियम को बनने के पश्चात् भारत की सम्पूर्ण डाक प्रणाली में सुधार हुआ और इसके प्रवधानों में अपनाकर डाक सेवाओं का सम्पूर्ण कार्य ब्रिटिश शासन ने भारतीय डाकघरों को हस्तांतरित कर दिया। इसी के साथ ही भारत वर्ष में डाक सेवा की शुरुवात हुई तथा भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन के लिए समुद्री डाक सेवा प्रारंभ की गई इसके पश्चात् वर्ष 1898 को भारतीय डाक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा आज तक भारतीय डाक सेवाओं को विनियमित किया जा रहा है।

देश भर में मान्य प्रथम डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया जिसके द्वारा वनज के आधार पर वहनीय और एक समान डाक दर उपलब्ध कराई गई फलस्वरूप डाक विभाग देश की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुआ। इस प्रकार डाक विभाग का राष्ट्र के समाजिक एवं आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी पहुँच देश के कोने-कोने तक विद्यमान है।

भारतीय डाक विभाग का प्रमुख क्रियाकलाप डाक की पोसेसिंग प्रेषक और उसका वितरण करना है। इसके साथ ही भारतीय डाक विभाग ने अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ भी प्रारंभ की हैं, जिसमें धन का प्रेषण जमा के रूप में बैंकिंग सेवाएँ तथा बिमा सेवाएँ प्रमुख हैं। वर्तमान में डाक विभाग द्वारा मनरेगा मजदूरों के भुगतान और समाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान दिया जा रहा है।

साहित्य की समीक्षा

1. **मालाकार, दीपांकर (2013).** वित्तीय समावेशन में भारतीय डाक की भूमिका, वित्तीय समावेशन को समावेशी समाज तथा समावेशी अर्थव्यवस्था के हमारे दृष्टिकोण के प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है कुछ मामलों में देश की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व किया है। उसी समय भारतीय डाकघर 1882 से समाज के सभी वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन से बहुत पहले ही भारतीय डाक सेवा को भारतीय ग्रामीणों का बैंकर होना चर्चा का विषय बन गया था और भारतीय डाक विभाग भी भारत में वित्तीय समावेशन के प्रणेता होने का दावा करते हैं।
2. **मुथुपंडी, डॉ. एम. (2014).** डाकघर बचत योजनाओं के प्रति जमाकर्ताओं की राय, वर्तमान समय में पूंजी बाजार में अनिश्चितता के साथ-साथ ब्याज दर में भी गिरावट आ रही है। लेकिन डाकघर की बचत योजनाएं उचित रिटर्न के साथ निवेशित धन की सुरक्षा हेतु उपयुक्त योजना हैं। जमाकर्ताओं की सेवा, डाकघर बचत योजनाओं की आधारशिला हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी बचत योजना की सफलता उसकी जमाकर्ताओं की सुरक्षा और लाभप्रदता आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह शोध पत्र लघु बचत क्षेत्र में आगे के शोध प्रयासों के लिए आधार बन सकता है।
3. **एस डॉ. उमाकांत और शर्मा डॉ. सोमा (2014).** डाक की बचत योजनाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा (विशेष संदर्भ में बेंगलूर शहर), नमूना निवेशकों का मुख्य उद्देश्य नियमित रिटर्न और कर लाभ के बाद पूंजी की सुरक्षा और संरक्षता हैं। अधिकांश निवेशक अपने नाम में अपना निवेश रखना चाहते हैं और 1 से 3 साल की अवधि के लिए निवेश करने में प्राथमिकता देते हैं। डाक विभाग द्वारा बनाए गए आधुनिक विज्ञापन तकनीकों का उपयोग करके नए निवेशकों को

आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए, इससे भारी धनराशि एकत्रित करने में मदद मिलेगी।

4. **कुमार, दिव्येश (2015).** डाकघर सेवाओं के संवर्धन का तुलनात्मक अध्ययन वित्तीय समावेशन—एक मेटा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि— भारत में डाक सेवाओं का आकलन करने के लिए, एक व्यक्ति के पास (औसतन) 4.61 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के समावेशी विकास के लिए लेन—देन का महंगा होना महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। नीति निर्माताओं के बेहतर समावेशन के लिए डाक नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए। भारतीय डाक सेवा अपने सबसे बड़े डाक सेवाओं और पोस्ट बैंक को अलग करके नेटवर्क सेवाओं से तालमेल हासिल कर सकती हैं।
5. **सरन्या बी. एवं कार्तिकेयन जी. बी. (2015).** डाकघर बचत योजनाओं के प्रति प्राथमिकताओं और संतुष्टि स्तर पर एक अध्ययन, समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि डाकघर में निवेश करने का प्रमुख कारण तीन कारकों से प्रभावित हैं जों कि आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए, निकट परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भविष्य और बच्चों की भलाई का ख्याल रखने हेतु डाक बचत योजनाओं में निवेश करने को प्राथमिकता देते हैं।

शोध प्रविधि

शोध प्रविधि किसी भी क्षेत्र में 'ज्ञान की खोज करना' या आंकड़ों को एकत्र करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए अपने शोध जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। भारतीय डाक विभाग के कार्यों पर आम जनता के द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाता है। मानव विकास समाज की श्रेष्ठतम् विशेषता है, वह नवीन वस्तुओं की खोज एवं पुरानी वस्तुओं, सिद्धान्तों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें, उसे शोध कहते हैं। शोध के अंतर्गत शोधकर्ता तर्कसंगत रूप से अपने आंकड़ों को जानने का प्रयत्न करता है और

तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन एवं विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों को सार्वजनिक रूप से की जाती है। शोध अध्ययन में अपने सिद्धांतों का सार्वजनिक रूप से बताया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय डाक विभाग ने सदैव जनता की सामर्थ्य के अनुसार डाक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

1. भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का विश्लेषण करना।
2. बिलासपुर जिले में भारतीय डाक विभाग द्वारा विभिन्न जमा योजनाओं का विश्लेषण करना।
3. भारतीय डाक विभाग के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान का विश्लेषण करना।

शोध की परिकल्पना

परिकल्पना शोध अध्ययन के पूर्वानुमान अध्ययन को बताती है। जिसके द्वारा शोधकर्ता उस विषय पर क्या शोध करेगा उसको बताती है।

1. H_a भारतीय डाक विभाग की सेवाएं ग्राहकों की संतुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान करना।
2. H_a बिलासपुर जिले में भारतीय डाक विभाग की सेवाओं एवं जमा योजनाओं से विभाग की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव होना।
3. H_a भारतीय डाक विभाग की सेवाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करना।

1. क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको मेल सर्विसेज उपलब्ध कराती है?

तालिका क्रमांक – 4.2

1. Does Indian Postal Department provide you mail services?					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AGREE	119	23.8	23.8	23.8
	DISAGREE	122	24.4	24.4	48.2
	STRONGLY AGREE	155	31.0	31.0	79.2
	STRONGLY DISAGREE	77	15.4	15.4	94.6
	NEUTRAL	27	5.4	5.4	100.0
	Total	500	100.0	100.0	

परिणाम

तालिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह ज्ञात होता है, कि भारतीय डाक विभाग द्वारा मेल सर्विसेज उपलब्ध कराती है कि नहीं जिसमें 54.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत है कि उन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा मेल सर्विस उपलब्ध कराते हैं जिससे उत्तरदाताओं को अपनी जानकारी को अप्रत्यक्ष रूप से मेल के द्वारा उपलब्ध करा पाते हैं। 39.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस तर्क से असहमत है, कि उन्हें भारतीय डाक विभाग मेल सर्विसेज उपलब्ध नहीं हो पाती है, तथा 5.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तर्क में अपनी तटस्थ व्यक्त की है। अतः प्राप्त आंकड़ों के आधार भारतीय डाक विभाग की मेल सर्विसेज आम लोगों के लिए लाभ दायक सेवा स्पष्ट होती है, जिससे उनको अपनी सूचनाएं सरलता से प्रदान करने हेतु इस मेल सर्विसेज का उपयोग करते हैं।

2. क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको पंजीकृत डाक उपलब्ध कराती है?

तालिका क्रमांक – 4.2

2. Does Indian Postal Department provide you registered post?					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AGREE	126	25.2	25.2	25.2
	DISAGREE	174	34.8	34.8	60.0
	STRONGLY AGREE	138	27.6	27.6	87.6
	STRONGLY DISAGREE	30	6.0	6.0	93.6
	NEUTRAL	32	6.4	6.4	100.0
	Total	500	100.0	100.0	

परिणाम

तालिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय डाक विभाग द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसमें 52.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा उन्हें पंजीकृत डाक सुविधा उपलब्ध कराती है, जिससे उत्तरदाताओं के द्वारा किसी प्रकार की सूचनाओं या वस्तुओं का पोस्ट किया जाता है तो इस रजिस्टर्ड के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह डाक उस विशेष व्यक्ति या कंपनी का है। 40.8 उत्तरदाता इस मत से असहमत है कि उन्हें भारतीय डाक विभाग से पंजीकृत डाक उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि यह सेवा प्रत्येक नागरिकों को सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती है, इसे विशेष सुविधाओं के लिए दिया जाता है जिसमें सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

3. क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको स्पीड पोस्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराती है?

3. Does Indian Postal Department provide you speed post facility?					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AGREE	174	34.8	34.8	34.8
	DISAGREE	72	14.4	14.4	49.2
	STRONGLY AGREE	151	30.2	30.2	79.4
	STRONGLY DISAGREE	71	14.2	14.2	93.6
	NEUTRAL	32	6.4	6.4	100.0
	Total	500	100.0	100.0	

परिणाम

तालिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, जिसमें 65 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत है कि उन्हें डाक विभाग द्वारा पोस्ट करने हेतु स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे की वस्तु या जानकारी कम समय में पहुंच जाती है। 28.6 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत है कि उन्हें डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, यह असुविधा ज्यादा तक ग्रामीण क्षेत्र में देखी गई है, क्योंकि उनके द्वारा डाक को डाकबॉक्स में डालकर पोस्ट करते हैं।

4. क्या भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको कोरियर सेवाएँ उपलब्ध कराती है?

4. Does Indian Postal Department provide you courier services?					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AGREE	166	33.2	33.2	33.2
	DISAGREE	94	18.8	18.8	52.0
	STRONGLY AGREE	113	22.6	22.6	74.6
	STRONGLY DISAGREE	100	20.0	20.0	94.6
	NEUTRAL	27	5.4	5.4	100.0
	Total	500	100.0	100.0	

परिणाम

तालिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय डाक विभाग द्वारा कोरियर सेवाएँ, जिससे 55.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत है कि उन्हें डाक विभाग द्वारा कोरियर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से उत्तरदाता भारी वस्तुओं को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान से सरलता से कोरियर कर पाता है, एवं उसको अन्य कोरियर सेवाओं की अपेक्षा भारतीय डाक विभाग में मूल्य कम खर्च होता है। 38.8 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत है, कि उन्हें डाक विभाग द्वारा कोरियर सुविधा का लाभ शीघ्र नहीं मिल पाता है, तथा उनके वस्तु को पहुंचाने समय अधिक लग जाता है, इसलिए कुछ उत्तरदाताओं के द्वारा निजी कोरियर सेवाओं का उपयोग करते हैं।

सुझाव

- भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही मेल सर्विसेज उत्तरदाताओं के अनुसार मेल सर्विस की गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं है जैसे अन्य मेल सर्विसेज संस्थाएं उपलब्ध कराती है, अतः सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग की मेल सर्विसेज के गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है, तथा इस मेल सर्विस को ऑनलाईन माध्यम से जोड़ा जाए जिससे आम उपभोक्ता को घर बैठे मेल सर्विस उपलब्ध हो सकें। इस मेल सर्विस की सुविधा भारत के प्रत्येक गांव में

उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वह भी इस लाभकारी सेवा का लाभ ले सकें।

- पंजीकृत डाक एक सेवा है जो पत्रों, दस्तावेजों, पार्सल और अन्य संबंधित वस्तुओं की अत्यधिक सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करती है। इस सेवा का लाभ प्रत्येक आम नागरिक को सरलता से उपलब्ध नहीं होती है। अतः भारतीय डाक विभाग द्वारा इस पंजीकृत डाक सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिया जाना चाहिए बिना की विशेष कारण के जिससे वह अपनी कुछ वस्तुओं को सुरक्षित डिलीवरी कर सकें, एवं प्रत्येक डाकघर को इस पंजीकृत डाक सेवा प्रदान करने की सुविधा देनी चाहिए। तथा लाभार्थी को अपनी डिलीवरी वस्तु को ट्रैक करने सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड की सुविधा उत्तरदाताओं की वस्तुओं को शीघ्र से पहुंचाया जा सकें उसके लिए प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल्य उस वस्तु की भार के अनुसार लिया जाता है, तथा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्पीड पोस्ट की सुविधा से अज्ञात है। अतः सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सुविधा के प्रति जागरूक ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, तथा स्पीड पोस्ट में लिये जा रहे शुल्क में कमी किया जाना चाहिए जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की जानकारी शीघ्र पहुंचाने हेतु अतिरिक्त मूल्य ना देना पड़े।
- भारतीय डाक विभाग द्वारा कोरियर सुविधा आम नागरिकों को अगर एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर भारी वस्तुओं, अधिक वस्तुओं को भेजना होता है तो कोरियर सेवा का लाभ लेते हैं किंतु इसमें समय अधिक लग जाता है, अतः सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग कोरियर सेवाओं का दर कम रखनी चाहिए, तथा प्रत्येक नागरिकों को कोरियर सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, एवं कोरियर का उपयोग कर रहे लाभार्थी की वस्तु शीघ्र समय में पहुंच सकें यह सुनिश्चित करना चाहिए।

भारतीय डाक की जमा आवर्ती की विशेषताएं

1. यह खाता नकद या चेक से खोला जा सकता है। यदि खाता खोलने के लिए चेक का उपयोग करने की तिथि जमा करने की होगी चेक की प्रस्तुति की तारीख के रूप में माना जाता है।
2. कोई भी राशि, न्यूनतम रु. 10/- प्रति माह या इसमें 5/- रुपये जमा किये जा सकते हैं। यह खाता खुलने का समय या उसके बाद नामांकन की अनुमति देता है।
3. जहां डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान है अब अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
4. पोस्ट ऑफिस किसी भी संख्या में आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है।
5. 10 साल के नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है, और उन्हें इसे संचालित करने की भी अनुमति है। बाद में बालिग होने पर अपने खाते में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय डाक विभाग की सेवाओं एवं जमा योजनाओं का आर्थिक अध्ययन बिलासपुर जिले में भारतीय डाक विभाग की सेवाओं और जमा योजनाओं का आर्थिक योगदान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि डाक विभाग की वित्तीय सेवाएं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डाकघर के माध्यम से संचालित बचत और निवेश योजनाएं जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), स्थानीय निवासियों के लिए एक सुरक्षित और सुलभ निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, जैसे बचत खाते, आवर्ती जमा (Recurring Deposit), और सावधि जमा (Fixed Deposit) योजनाएं, ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। इन योजनाओं ने न केवल स्थानीय लोगों को सुरक्षित बचत के साधन प्रदान किए, बल्कि उन्हें भविष्य

की योजनाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा भी दी। डाक विभाग की बीमा योजनाएं, जैसे डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ने भी इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाई हैं। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज का विस्तार भी हुआ। डिजिटल क्रांति और निजी बैंकों की प्रतिस्पर्धा ने पारंपरिक सेवाओं को चुनौती दी है। डाकघर सेवाओं को अधिक तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण और ग्राहक सेवा में सुधार की जरूरत है ताकि वे निजी और सार्वजनिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारतीय डाक विभाग की जमा योजनाओं और सेवाओं ने बिलासपुर जिले में आर्थिक स्थिरता और वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, बदलती आर्थिक परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में सफल बने रहने के लिए इन सेवाओं में नवाचार और तकनीकी उन्नयन की अत्यधिक आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मालाकार दीपांकर (2013) वित्तीय समावेशन में भारतीय डाक की भूमिका, *Journal Of Humanities And Social Science*, 6(4) : पृष्ठ क्रमांक-4.
2. मुथुपंडी, डॉ. एम. (2014) डाकघर बचत योजनाओं के प्रति जमाकर्ताओं की राय, *Shanlax International Journal of Commerce*, 2(2) : पृष्ठ क्रमांक-95.
3. एस डॉ. उमाकांत और शर्मा डॉ. सोमा (2014) डाक की वापसी क्षमता पर विश्लेषणात्मक समीक्षा बचत योजनाएँ विशेष संदर्भ में बैंगलोर शहर, *Indian Journal Of Applied Research*, 4(6) : पृष्ठ क्रमांक-314.
4. कुमार दिव्येश (2015) डाकघर सेवाओं के संवर्धन का तुलनात्मक अध्ययन वित्तीय समावेशन-एक मेटा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, *International Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 2(3) : पृष्ठ क्रमांक-11.
5. सरन्या बी. एवं कार्तिकेयन जी. बी. (2015) डाकघर बचत योजनाओं के प्रति प्राथमिकताओं और संतुष्टि स्तर पर एक अध्ययन, *International Journal Of Management*, 6(1) : पृष्ठ क्रमांक-775.
6. एम.वी.जाशमीन और जोसेफ एम.ए (2018) भारतीय डाक में आवर्ती जमा धारकों पर एक अध्ययन कोठामंगलम नगर पालिका के लिए विशेष संदर्भ, *Indian Journal of Appiled Research*, 8(12) : पृष्ठ क्रमांक-19
7. ग्रेवाल विजय और यादव दीपिका (2021) डाकघर द्वारा संचालित विभिन्न कर बचत योजनाओं का अध्ययन, *International Journal of Innovation in Engineering Research & Management*, 08(03) : पृष्ठ क्रमांक-67.
8. मिंज मनोज और पांडेय पूजा (2021) वित्तीय समावेशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की भूमिका, *Kala Sarovar*, 24(3) : पृष्ठ क्रमांक-70.
9. प्रकाश चोक्कमरेड्डी, आर. रेड्डी कसीरेड्डी संदीप और स्वाति एम (2023) तेलंगाना के जुड़वां शहरों के संदर्भ में डाकघर बचत योजनाओं के प्रति निवेशकों की

धारणा और रवैया, *International Journal of Research and Analytical Reviews*,
10(2) : पृष्ठ संख्या – 949 |

10. https://www.indiapost.gov.in/Documents/PostalHistory/POSTAL_SYSTEM_DURING_MAURYA_PERIOD_321-297%20BC.pdf
11. https://www.indiapost.gov.in/Documents/PostalHistory/POSTAL_SYSTEM_DURING_MUGHAL_PERIOD_1504-30.pdf
12. https://www.indiapost.gov.in/Documents/PostalHistory/POSTAL_SYSTEM_DURING_BRITISH_ERA_1727-1854.pdf